www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 173 | जौनपुर शनिवार, 07 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

नेपाल में बारात ले जा रही बस हादसे का शिकार, 8 लोगों की मौत

काठमांडू, (एजेंसी)। नेपाल के बैतडी जिले में गुरुवार शाम एक शादी की बारात ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। डीएसपी दीपक कुमार राय ने आईएएनएस को बताया, "शादी की बारात ले जा रही बस गुरुवार को रात लगभग 8 बजे जिले के पुचौंडी नगरपालिका में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि इस हादसे में करीब 45 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 16 को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार मिला, जबकि बाकी को बेहतर सुविधाओं वाले अस्पतालों में भेजा गया। राय ने कहा कि दुल्हन और दूल्हा सुरक्षित रहे क्योंकि वे दूसरी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना का सही कारण तुरंत पता नहीं चल सका। जिलाधिकारी कृष्णा थापा ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में लगभग 60 लोग सवार थे। उन्होंने कहा कि नेपाल सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया।विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, नेपाल में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक हानि 2007 से तीन गुना बढ़ गई है और यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.5 प्रतिशत के बराबर है।

बंगाल की सभी 294 सीटों पर अकेले उतरेगी पार्टी

कोलकाता, (एजेंसी)। कांग्रेस ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे या तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का सीट–साझाकरण समझौता नहीं करेगी। यह निर्णय गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया गया।पश्चिम बंगाल से पार्टी के प्रतिनिधियों में वर्तमान राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सुवंकर सरकार, पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और पांच बार के पूर्व लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी, और पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सदस्य ईशा खान चौधरी शामिल थे। राजधानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद, कांग्रेस महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घोषणा की कि एआईसीसी आगामी विधानसभा चुनाव राज्य में किसी भी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन किए बिना स्वतंत्र रूप से लड़ेगी।खड़गे और मीर के अलावा, बैठक में उपस्थित अन्य राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेताओं में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल शामिल थे। मीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन या सीट बंटवारे की व्यवस्थाओं के हमारे पिछले अनुभवों ने राज्य में जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत की जमीन तैयार कर रहे है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विश्वासघात करने में हमारे देश के अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा। इस देश में 10 करोड़ किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। छोटे किसानों की तरफ कभी देखा नहीं गया, लेकिन हमारे दिल में छोटे किसानों के प्रति एक दर्द था, जमीनी हकीकतों से परिचित थे और उसी के कारण हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आए और अब इतने कम समय में हमारे छोटे किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए हमने दिए हैं।प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन की कार्यशैली रही है– लटकाना, अटकाना, भटकाना। ये लोग सिर्फ जीप और खच्चर वाला मॉडल ही जानते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले सरदार वल्लभभाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बांधने की कल्पना की थी। विषय तो पक्का हो गया, सरदार साहब नहीं रहे। नेहरू ने शिलान्यास किया, लेकिन उसका उद्घाटन मैंने किया जब मैं प्रधानमंत्री बना... ये इनका (कांग्रेस) हाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत की जमीन तैयार कर रहे हैं और कांग्रेस कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करती है? क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ कल्पना ही कर सकती है। कार्यान्वयन से उनका कोई लेना–देना नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला बोगीबील पुल, एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजना है, जिसमें दशकों से देरी हो रही थी। प्रगति पहल के तहत हमने इसकी प्रगति की समीक्षा की और परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि 140 करोड़ देशवासी इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपने देशवासियों पर भरोसा है।

पैतृक गांव के दौरे के दौरान भावुक हुईं राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को ओडिशा के मयूरभंज जिले के अपने पैतृक गांव में दिवंगत पति श्याम चरण मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय भावुक हो गईं। ओडिशा के छह दिवसीय दौरे पर आईं राष्ट्रपति ने अपने गांव पहाड़पुर का दौरा किया और दिवंगत पति तथा दोनों पुत्रों लक्ष्मण व सिपुन की स्मृति में बने एसएलएस मेमोरियल पहुंचीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने व्यक्तिगत जीवन में कई त्रासदियों का सामना किया है। वर्ष 2009 में उनके बेटे लक्ष्मण, 2012 में बेटे सिपुन और 2014 मेंपति की मृत्यु हो गई। इसी अवधि में उनकी मां और एक भाई का भी निधन हो गया था। एसएलएस मेमोरियल में एक आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जहां आदिवासी, वंचित और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पिछले कुछ दिन में राष्ट्रपति ने अपने दिवंगत परिजन की आत्मा की शांति के लिए जाजपुर और पुरी में पिंडदान की रस्में भी निभाईं। बृहस्पतिवार को उन्होंने

रायरंगपुर के एक जगन्नाथ मंदिर में हिंदू परंपराओं के अनुसार ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने जंगली क्षेत्र में स्थित संथाल समुदाय के उपासना स्थल 'जाहिरा' का भी दौरा किया और संथाली देवता मारंग बुरु की पूजा–अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मौजूद कमांडो 'जाहिरा' में प्रवेश से पहले पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अपराह्न करीब 3रू30 बजे जशिपुर के पास अनुकूलपुर मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरा। यहांवन मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया, सांसद नबा चरण माझी तथा वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं खड़ी रहीं।

वेब सीरीज घुसखोर पंडत पर भड़कीं मायावती

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज घुसखोर पंडत पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसमें ब्राह्मण समुदाय को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का चित्रण अपमानजनक है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने लखनऊ पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज एफआईआर का भी समर्थन किया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि यह अत्यंत दुख और चिंता का विषय

है कि हाल के दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि अब फिल्मों में भी श्पंडितश को रिश्वतखोर आदि के रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे पूरे देश में उनका अपमान और अनादर हो रहा है। इससे ब्राह्मण समुदाय में तीव्र आक्रोश फैल गया हैय हमारी पार्टी भी इसकी कड़ी निंदा करती है। पोस्ट में लिखा था कि केंद्र सरकार को जाति–भेदभाव वाली इस फिल्म (वेब सीरीज) श्घुसखोर पंडितश पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिएय यह बसपा की मांग है। साथ ही, लखनऊ पुलिस द्वारा इस संबंध में एफआईआर दर्ज करना उचित कदम है। आज लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता नीरज पांडे और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया था कि श्घुसखोर पंडितश का शीर्षक और विषयवस्तु धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं।

केंद्रीय बजट से लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा : सीएम भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को कहा कि गुजरात को केंद्रीय बजट 2026–27 से काफी लाभ होने वाला है, जो आर्थिक विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पटेल ने बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट तीन प्रमुख प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित है, जिनमें सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय समृद्धि में

सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास को आगे बढ़ाना शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में बायो–फार्मा स्ट्रेंथ प्रोग्राम के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायो–फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते, गुजरात को भी इस पहल से लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि वस्त्र क्षेत्र को समर्थन देने वाली छह नई योजनाएं राज्य के वस्त्र उद्योग को गति प्रदान करेंगी।पटेल ने गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले 42 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में 'चौंपियन एमएसएमई' बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई फंड की घोषणा की गई है, जिससे इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ और बेहतर तरलता मिलेगी। बुनियादी ढांचे के बारे में पटेल ने कहा कि गुजरात चार संयंत्रों के साथ एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में आगे बढ़ रहा है और बजट में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से लाभान्वित होगा।

हेमा मालिनी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सांसद हेमा मालिनी ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा, "इस अवसर पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।" इससे पहले, विश्व कैंसर दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 'जन–जन जागे, कैंसर भागे' अभियान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ हिस्सा लिया।मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास

और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई केवल इलाज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए समाज के सामूहिक सहयोग और मानवीय संवेदनशीलता की भी जरूरत है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर धीरे–धीरे दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनते जा रहे हैं। फिलहाल, राजधानी में करीब 350 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं, जहां मुंह, स्तन और सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त जांच के साथ–साथ दवाइयां, टीकाकरण और जरूरी जांच सुविधाएं दी जा रही हैं।उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है और अब तक 43 करोड़ से अधिक लोग इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। दिल्ली में भी लाखों लोग इस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि देशभर में 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कई दवाइयां 90 प्रतिशत तक सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। आम लोगों तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां पहुंचाने के लिए दिल्ली में भी इन केंद्रों का लगातार विस्तार किया जा रहा है।सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रमुख केंद्रीय अस्पतालोंकृ एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पतालकृके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे चिकित्सा ढांचे को मजबूत किया जाएगा, आधुनिक उपकरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को बेहतर, सुलभ और सम्मानजनक इलाज मिल सकेगा।

विपक्ष की दिक्कत, सवालों के जवाब नहीं सुनना चाहते : चिराग पासवान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष की दिक्कत यह है कि वे सवाल तो उठाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष ने जितने सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत तो रखनी चाहिए। लोकसभा में पीएम बोलना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण संभव नहीं हो पाया। राज्यसभा में जब वे बोल रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। विपक्ष की असली दिक्कत यह है कि वे सवाल तो उठाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब सुनना नहीं चाहते। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप कठिन से कठिन सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मर्यादित रहकर। जरूरी नहीं है कि कुर्सी पर चढ़ना पड़े। आप कड़े से कड़े विरोध को भी मर्यादित शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की जरूरत है कि कैसे मर्यादित तरीके से अपने शब्दों में सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। अगर नेता विपक्ष भी मर्यादित होकर सवाल पूछते तो उनके सवालों के जवाब भी मिलते। सवाल यह है कि विपक्ष सवाल तो पूछते हैं, लेकिन जवाब लेने के लिए तैयार नहीं। लोकसभा में पीएम मोदी की सीट के आसपास विपक्षी महिला सांसदों के व्यवहार पर चिराग पासवान ने कहा कि यह एक गंभीर घटना थी।

परीक्षा पे चर्चा अब राष्ट्रीय आंदोलन, स्कूली परीक्षा परिपक्व होने का एक पड़ाव है : सीएम धामी

देहरादून, (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशविला रोड स्थित सेंट एंग्नेस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्परीक्षा पे चर्चाश कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के श्परीक्षा पे चर्चाश के नौवें संस्करण से जुड़ा है। यह आयोजन अब केवल संवाद नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। पीएम मोदी का संदेश हमें यह सिखाता है कि परीक्षा जीवन की एक कड़ी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण जीवन नहीं। सीएम धामी ने अपने स्कूली जीवन

के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि स्कूल का समय अमूल्य होता है, जो दोबारा लौटकर नहीं आता। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ–साथ खेल और अन्य गतिविधियों में भी निरंतर प्रतिभाग करना चाहिए। परीक्षा एक अवसर है, जिसमें छात्र एक योद्धा की तरह पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और शांति के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही काबिलियत नहीं, जीवन में और भी अनेक लक्ष्य होते हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से लक्ष्य तय कर प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ने तथा परीक्षा के दबाव से मुक्त रहकर सकारात्मक सोच के साथ सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया। साथ ही अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें और उनकी तुलना दूसरों से न करें। इसके साथ सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्श्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज श्परीक्षा पे चर्चाश कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के विद्यार्थियों को नई सोच, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए।

रूस से तेल खरीद पर भारत ने स्थिति को किया स्पष्ट, लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत ने साफ किया है कि 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी आधार पर कच्चे तेल की खरीद को लेकर रणनीति तय की जाती है। विदेश मंत्रालय का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के कुछ दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका व वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत की ऊर्जा नीति का मूल उद्देश्य देश की जरूरतों को सुरक्षित और स्थिर तरीके से पूरा करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा खरीद के संबंध में उठाया जाने वाला हर कदम राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में

रखकर ही तय किया जाता है।प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जहां तक भारत की ऊर्जा खरीद का सवाल है, सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने आगे कहा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और बाजार की स्थितियों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है। "बाजार की स्थितियों और वैश्विक घटनाक्रम को देखते हुए ऊर्जा खरीद में विविधता लाना हमारी दीर्घकालिक रणनीति का मुख्य आधार है। भविष्य में भी हम इसी सिद्धांत का पालन करेंगे।" जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत वेनेजुएला समेत कच्चे तेल की आपूर्ति के किसी भी नए और व्यवहार्य विकल्प पर विचार करने के लिए खुला है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि रूस से तेल खरीद में कोई तत्काल बदलाव किया जाएगा या नहीं।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते की घोषणा की थी। इसी दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है ।

संपादकीय

नई दवाओं के विकास

अनुसंधान एवं परीक्षण की गतिविधियों को नौकरशाही सुस्ती से मुक्त करना सही दिशा में कदम है। लेकिन इसे सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि दवा कंपनियां नियमों में दी जा रही रियायत का बेजा फायदा ना उठाएं। भारत सरकार ने नई दवाओं के विकास के लिए हरी झंडी देने के नियम आसान बनाए हैं। इसके लिए नई औषधि एवं क्लीनिकल ट्रायल के 2019 में बने नियमों में बदलाव किया गया है। मकसद नई दवाओं के परीक्षण में लगने वाले समय को घटाना और संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। पहले ऐसे कार्यों के लिए केंद्रीय औषधि प्रमाणन नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य था। अब कंपनियां कुछ श्रेणियों की दवाओं को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सीडीएससीओ को महज ऑनलाइन सूचना देकर परीक्षण शुरू कर सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस बदलाव से कम–से–कम 90 दिन की बचत होगी। दवा कंपनियां लंबे समय से ऐसे बदलाव की मांग कर रही थीं। विनियमन प्रक्रिया की धीमी गति को वे अपने लिए बड़ी रुकावट मानती रही हैं। अतरू अनुसंधान एवं परीक्षण की गतिविधियों को नौकरशाही सुस्ती से मुक्त करना सही दिशा में कदम है। लेकिन इसे सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि कंपनियां नियमों में ढीलेपन का बेजा फायदा ना उठाएं। हालांकि भारतीय दवा उद्योग की दुनिया में ऊंची साख है, लेकिन हाल के वर्षों में कंपनियों द्वारा विनियमन प्रक्रिया में ढिलाई का लाभ उठाने के कई मामलों सामने आए हैं। कफ सिरप जैसी दवाओं से मिलावट की घटनाओं से भारतीय औषधि उद्योग पर कलंक लगा है। आम धारणा है कि भारत में निगरानी की व्यवस्था पश्चिमी देशों में मौजूद विनियम से कमजोर है। इसी कारण भारत में बनी जेनरिक दवाओं को ब्रांडेड दवाओं से अक्सर कमतर समझा जाता है। इसके बावजूद भारत में बनी दवाओं और वैक्सीन का दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है, तो उसकी वजह इनका किफायती होना है। दवा उत्पादन के लिहाज से भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के लिहाज से 14वें स्थान पर आता है। देश में तीन हजार से ज्यादा दवा कंपनियां और साढ़े दस हजार फैक्टरियां हैं। लगभग 60 जेनरिक ब्रांड यहां उत्पादित होते हैं। इस कारोबार ने दशकों के दरम्यान इतना विशाल आकार ग्रहण किया है, तो उसमें विश्वसनीयता एक निर्णायक पहलू रही है। नए बदलावों के साथ इस पर कोई समझौता नहीं हो, इसे अवश्य सुनिश्चित करना होगा।

जनरल नरवणे की किताब में चीन पर ऐसा क्या लिखा है

अभिनय

संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो परंपरा और मर्यादा का क्षण होता है उसे भी आज राहुल गांधी ने टकराव और सनसनी का मंच बना डाला। दरअसल आज राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवने की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा कि डोकलाम में चार चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका भी। पर राहुल कहां रुकने वाले? राहुल बोलते रहे। स्पीकर डांटते रहे। बार–बार सदन की कारवाही को स्थगित करनी पड़ी। राहुल ने आरोप लगाया कि वह नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। तो सत्ता पक्ष ने कहा कि देश की सुरक्षा पर आधी अधूरी बात बिना प्रमाण के दावा और अपुष्ट किताबों का जिक्र यह बहस नहीं भ्रम फैलाने की कोशिश है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऐसा कितनी ही दफा होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने खड़े हो और सामने से गृह मंत्री जवाब दे रहे हो और जवाब तल्ख लहजे में आ रहा हो। ऐसा कितनी ही दफा होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हों और उधर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो जाएं जवाब देने में और जवाब तल्ख लहजे में आता है और दोनों तरफ से तल्खी बराबर की थी। दोनों तरफ से एकदम बहस हुई और उस बहस में एक किताब केंद्र में थी। उस किताब को लेकर राहुल गांधी ने संसद के पटल पर बात की और उसके बाद जो रूप दिखा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का वो अपने आप में एक देखने लायक चीज थी कि किस तरीके से संसद में जो देश के टॉप लीडर्स कहे जाते हैं उनकी आपस में नोकझोंक होती है तू तू मैंम होती है और वो किताब जिस किताब का राहुल गांधी ने जिक्र किया वो किताब आई कहां से, किताब में ऐसा क्या लिखा है कि उस किताब का जिक्र करते ही अमित शाह भड़क गए। उस किताब का जिक्र करते ही राजनाथ सिंह भड़क गए। पूरी बीजेपी पूरी बीजेपी का सत्ता पक्ष का खेमा भड़क गया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद (एमएम) नरवणे की लिखी किताब का नाम है डेस्टिनी ऑफ फोर स्टार मतलब कि जो चार सितारे मतलब डेस्टिनी फोर स्टार मतलब जो जनरल होते हैं उनकी नियति या उनकी डेस्टिनी क्या होती है? लेकिन किन बिंदुओं पे आपत्ति है और किताब क्या रिलीज हुई है? नहीं रिलीज हुई है? किताब का क्या स्टेटस है? किताब को लेकर क्या विवाद है? ऐसा लिखा क्या गया है? आज का एमआरआई स्कैन इसी पर करेंगे। जब भी कोई किताब पब्लिश होने वाली होती है तो उस उस किताब के कुछ जो है हिस्से वो जर्नलिस्ट के पास में भेजे जाते हैं। पत्रकारों के पास में भेजे जाते हैं कि उसको पढ़ के पहले उसके ऊपर कुछ अर्ली कमेंट करें तो रीडर्स की उसमें दिलचस्पी बने और वो उस किताब को खरीदें। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल अप्रैल 2021 तक ये इस अपने पद पे रहे थे। 2 साल का इनका कार्यकाल था और उसके बाद में जब वो रिटायर हो के आए हैं तो उन्होंने पहली अपनी किताब लिखी उसका नाम था फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी। मतलब फोर स्टार क्योंकि जो सेना चीफ होता है वह फोर स्टार जनरल होता है। फोर स्टार जनरल उसको कहा जाता है। फील्ड मार्शल फाइव स्टार जनरल होता है। जिस समय किताब के कुछ हिस्से हमारे पास में आए थे। उस समय विवाद जो था वो दरअसल अग्निवीर स्कीम पर था। इस किताब को लॉन्च अप्रैल 2024 में होना था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अग्निवीर स्कीम को विपक्ष ने बहुत अलग–अलग तरीकों से उठाया था और कहा था कि नौजवानों को एक तरीके से सेना में जो रोजगार था उससे उसे महरूम रखने की उससे हटा देने की जो है ये साजिश है। इसके ऊपर खासा विवाद हुआ था। इसमें जनरल नारायण ने अपने किताब में कोट अनकोट ये लिखा था कि सेना के लिए घटनाक्रम जो है अग्निवीर स्कीम का लांच करना 2022 में वो चौंकाने वाला था। लेकिन नौसेना और वायु सेना के लिए तो ऐसा था जैसे बिल्कुल आसमान से बिजली गिरी है। ये उन्होंने लिखा था और इसको बार–बार यह विवाद हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक किताब जनवरी 2025 तक छपकर पब्लिक डोमेन में आने वाली थी। लेकिन फिर इसे रिव्यू के लिए भेज दिया गया। क्योंकि वह सेना प्रमुख थे तो आर्मी और रक्षा मंत्रालय के पास किताब रिव्यू के लिए भेजी गई। इस बात को 2 साल हो गए। इसी बीच पिछले दिनों बंतंअंद मैगजीन में इस अप्रकाशित किताब में लिखी बातों का जिक्र करते हुए एक डिटेल लेख छापा गया। उसमें लिखा कि भारतीय सेना की नॉर्थ कमान के तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 की रात 8रू15 बजे एक फोन कॉल आया। चार चीनी टैंक, पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला की ओर ऊपर बढ़ रहे थे। चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय सेना की पोस्ट से कुछ सौ मीटर की दूरी पर थे। इसके बाद जनरल नरवणे ने देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को फोन करना शुरू किया। वे यही पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। इसमें लिखा है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई साफ निर्देश नहीं मिला। चीनी टैंक रुके नहीं थे। वे चोटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर रह गए थे। किताब में नरवणे ने लिखा है कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। रात 10रू30 बजे रक्षा मंत्री का फोन आया। टॉप लीडरशिप से निर्देश सिर्फ एक पंक्ति का था श्जो उचित समझो, वो करो। किताब के हवाले से कहा गया है

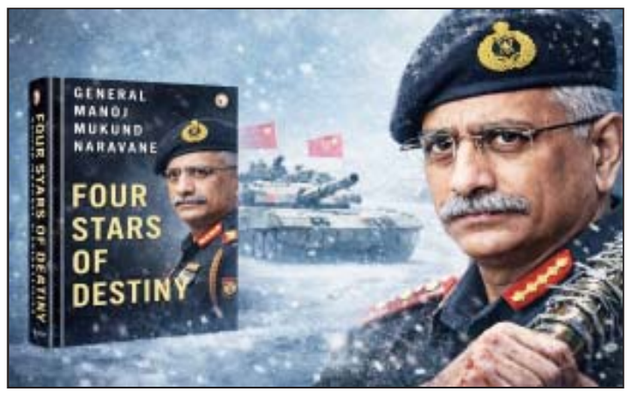

कि अगस्त 2020 में गलवान की झड़प कोई अचानक या अप्रत्याशित घटना नही थी, बल्कि यह चीन की ओर से कई हफ्तों तक बढ़ती आक्रामकता का नतीजा थी। स्थानीय कमांडर पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे और उन्होंने स्थिति को कमतर दिखाने की कोशिश की। ये भी लिखा है कि हमारे कई जवान जो या तो रास्ता भटक गए थे या फिर च्र। की ओर से कुछ समय के लिए बिना खाना और इलाज दिए रोके गए थे, वापस अपने बेस पर लौट आए। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की ऑटोबायोग्राफी श्फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीश क्या रिलीज होगी या नहीं? जब से श्फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीश की रिलीज रूकी तबसे ही यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों यह रूकी और कब पब्लिश होगी। पिछले साल अक्टूबर में खुशवत सिंह लिट फेस्ट में जब एक गेस्ट की तरफ से जनरल नरवणे से ये पूछा गया कि आपकी किताब अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुई और पब्लिश क्यों नहीं हुई जो जनरल नरवणे ने हसते हुए जवाब दिया कि मैं भी ये जानना चाहता हु। ये पब्लिशर का काम है कि वे रक्षा मंत्रालय से परमिशन लें। ये अभी अडर रिव्यू है। लेकिन क्या रक्षा मंत्रालय इसका रिव्यू कर रहा है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है? इसका मंत्रालय की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। न ही भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया कि क्या उन्हें इस किताब से कोई आपत्ति है। एक अधिकारी ने बताया कि हर सरकारी कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेनाओं के लोग भी शामिल होते हैं, वे ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट से बंधे होते हैं। सर्विस में रहते हुए और रिटायर होने के बाद भी उन्हें इसका पालन करना होता है। अगर वे ऐसी कोई बातें लिखते हैं या ऐसा कुछ बनाते हैं जो उनकी सर्विस से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए उन्हें सभी जरूरी इजाजत लेनी होती है। ये किताब या लेख या जो भी वे प्रड्यूज कर रहे है उसके कंटेंट पर निर्भर करता है।

विकसित भारत के अग्रदूतों के भविष्य को संवारना

धर्मेंद्र प्रधान

इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का आयोजन भारत की शिक्षा यात्रा में शांत लेकिन निर्णायक परिवर्तन को रेखांकित करता है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिकल्पित यह पहल, जो 2018 में एक एकल वार्षिक संवाद के रूप में प्रारंभ हुई थी, आज स्वाभाविक रूप से एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब यह एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक प्रयास बन गई है, जिसमें विद्यार्थियों के समग्र कल्याण को केंद्र में रखा गया है और माता–पिता व शिक्षक इस साझा उत्तरदायित्व के सक्रिय सहभागी हैं। इस वर्ष की सहभागिता का पैमाना इस पहल की गहराई को दर्शाता है। 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ परीक्षा पे चर्चा, पूर्व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब जन–संपर्क से आगे बढ़कर सामूहिक स्वामित्व की एक महत्वपूर्ण अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। यह अभूतपूर्व सहभागिता सक्षम वातावरण निर्मित करने के सामूहिक संकल्प को प्रतिबिंबित करती है, जहाँ प्रत्येक बच्चा सीख सके, विकसित हो सके और सही मायनों में फल–फूल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का शिक्षा, अध्ययन और परीक्षा से जुड़े तनाव जैसे विषयों पर विद्यार्थियों के साथ संवाद सहानुभूति, व्यवहारिकता और प्रेरक नेतृत्व का विशिष्ट समन्वय प्रस्तुत करता है। सरलता, अनुशासन, आशावाद और मानव क्षमता में गहरी आस्था से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व ने लाखों बच्चों के मन पर गहरा और स्थायी प्रभाव अंकित किया है। औपचारिक प्रोटोकॉल की जटिलताओं से परे जाकर विद्यार्थियों से मार्गदर्शक, मेंटर और शुभचिंतक के रूप में जुड़ने की सहज क्षमता प्रधानमंत्री को विशिष्ट बनाती है। उनकी संवादात्मक, कथात्मक और आत्मीय शैली विद्यार्थियों को यह अनुभव कराती है कि उनकी बातें सुनी और समझी जा रही हैं। वे गर्मजोशी, हास्य और प्रामाणिकता के साथ संवाद करते हैं तथा अक्सर अपने जीवन के अनुभवों से उदाहरण लेकर धैर्य, एकाग्रता और आत्मबल जैसे व्यापक जीवन मूल्यों को सरलता से प्रस्तुत करते हैं। यह व्यक्तिगत स्पर्श परीक्षा से जुड़े दबावों को सहज बनाते हुए आश्वस्त और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है, जहाँ विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता की पहचान इस प्रयास के केंद्र में एक सरल किंतु अत्यंत सशक्त सत्य निहित हैरू हर बच्चा विशिष्ट है। प्रत्येक बच्चा अलग तरह से सीखता है, अपनी गति से आगे बढ़ता है और अपने भीतर ऐसी प्रतिभाएँ समेटे होता है, जिन्हें अंकों या रैंक तक सीमित नहीं रखा जा सकता। परीक्षाएँ अपनी प्रकृति के अनुसार, बच्चे की क्षमता के सीमित पहलू को ही दर्शाती हैं। समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के माध्यम से ही उसकी वास्तविक सृजनात्मकता और उत्कृष्टता का विकास होता है। कोई बच्चा गणित में उत्कृष्टता दिखा सकता है, कोई कलात्मक कल्पना में निपुण हो सकता है, और कोई करुणा के साथ संवेदनशील चिकित्सक बनने की क्षमता रखता है। ये भिन्नताएँ किसी तरह की कमी नहीं हैंय बल्कि यही विविध, सशक्त और नवोन्मेषी समाज की आधारशिला हैं। यह दर्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के मूल में निहित है। इसके ढाँचे के अंतर्गत शिक्षण–पद्धतियों, पाठ्यक्रमों और मूल्यांकन प्रणालियों को एक वास्तविक बाल–केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप पुनर्गठित किया जा रहा है, जहाँ शैक्षणिक अध्ययन के साथ–साथ सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शारीरिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। प्रारंभिक वर्षों में खेल–आधारित शिक्षण पर इसका जोर इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जिज्ञासा और आनंद ही आजीवन सीखने की सबसे सशक्त आधारशिलाएँ हैं। शिक्षा के आरंभिक वर्षों में मातृभाषा में शिक्षा देने का उद्देश्य बच्चों को अवधारणाओं की बेहतर समझ प्रदान करना है, जबकि बहुभाषिकता पर दिया गया बल ऐसी पीढ़ी के निर्माण की परिकल्पना करता है जो अपनी सांस्कृतिक और भाषायी जड़ों के प्रति विश्वास रखती हो तथा भारतीय ज्ञान परंपराओं को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने में सक्षम हो। मूल्यांकन संबंधी सुधार भी इसी उद्देश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। पहली बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएँ अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएँगी, जिससे विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा और उच्च–दबाव वाली एकल परीक्षा से जुड़ा तनाव कम होगा। 360–डिग्री समग्र प्रगति कार्ड लागू किए गए हैं, जो केवल बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियों का ही आकलन नहीं करते, बल्कि उसके सामाजिक–भावनात्मक और शारीरिक विकास को भी समग्र रूप से दर्ज करते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि तंदुरुस्ती सीखने का अभिन्न अंग है, प्रत्येक सीबीएसई विद्यालय में सामाजिक–भावनात्मक परामर्शदाताओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जो विद्यार्थियों को शैक्षणिक और भावनात्मक तनाव के प्रबंधन में निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे। अंत में, हमारे समक्ष उत्तरदायित्व स्पष्ट हैकृबच्चों को किसी एक साँचे में ढलने के लिए विवश नहीं करना चाहिए।

भारत–अमेरिका ट्रेड डील के बीच कई सवाल बाकी

अभिनय

पाकिस्तान वाले जो अमेरिका जाकर कह रहे थे कि चांद ले लो, तारे ले लो, सूरज ले लो हमसे जो मांगोगे वो दे देंगे। बस साथ दे दो। आज यह खबर उनको भी परेशान कर रही होगी। वो तो ये मान रहे थे कि अच्छा हो रहा है अमेरिका और भारत दूर हो रहे हैं। वो अपने करीब आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की सारी मेहनत पर पलीता लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया जिसने भारतीय मार्केट को भी बूम बूम कर दिया। पीएम मोदी चीन की यात्रा पर गए थे। जहां पर कि पुतिन के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी और राष्ट्रपति पुतिन का भी भारत में दौरा हुआ था। तो भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि वो चाहता है कि मल्टी लेटरल फोरम हो और उसमें किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी भारत की ना रहे। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश भारत का है। अमेरिका भी इस बात को भांप गया था कि भारत किसी दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लागू टैरिफ को घटाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर कर टैरिफ कट और भारत–अमेरिका ट्रेड डीलध पर सहमति बनने का ऐलान किया। ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, उन्हें ट्रंप के साथ बात करके खुशी हुई। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर घटा हुआ 18: टैरिफ लगेगा। पीएम मोदी ने कहा, जब दो बड़ी इकॉनमी और दुनिया के दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी साथ आती है तो कई साझे अवसर और सहयोग, लोगों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हालांकि भारत की ओर से तुरंत इस डील के बारे में आधिकारिक रूप से विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। 3 फरवरी 2026 की रात 9रू16 बजेः अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की फोन बातचीत की जानकारी दी। पिछले एक साल में भारत ने 6 देशों से डील की। ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड, ईयू, ईएफटीए ब्लॉक और अमेरिका। भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को भी मदर ऑफ ऑल डील की संज्ञा दी गई है। इसके लिए भारत ने कई दशक प्रयास किया। ट्रंप ने भारत के खिलाफ पहले 25: टैरिफ लगाया था और बाद में पिछले साल अगस्त में रूसी तेल खरीदने के नाम पर और 25: टैरिफ लगा दिया था। इसकी बड़ी चोट भारत के लेदर, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड जूलरी जैसे ज्यादा श्रम की जरूरत वाले सेक्टरों से निर्यात पर पड़ रही थी। दिसंबर में अमेरिका को निर्यात सालभर पहले से 1.83: घटकर 688.6 करोड़ डॉलर रहा। अमेरिका का 50: टैरिफ 27 अगस्त को लागू हुआ था। उसके बाद सितंबर से दिसंबर तक अमेरिका को निर्यात 25.6 बिलियन डॉलर का रहा। भारत पर ही सबसे पहले टेरिफ बढ़ाया गया था। ये 25: फिर कहा गया और बढ़ा देंगे। कंपनियों पर बैन लगाया गया। भारत ने स्वाभिमान की जीत तो दर्ज की है। यह तो आज स्पष्ट हुआ है। भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था है मजबूत है। भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा देश है। भारत इस वक्त जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। तो दुनिया जानती है कि भारत पर जो है पैसा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही बजट में हमने ये देखा कि वित्त मंत्री निमला सीतारमण ने इस बात का खास तौर से ध्यान दिया कि ट्रंप के टेरिफ के कारण भारत के जो जो सेक्टर प्रभावित हो रहे थे उन सब सेक्टर्स को राहत दी गई है। तो ये भी एक बड़ा संदेश था अमेरिका के लिए और उन एफआईआई के लिए जो अपना पैसा लगातार भारत से निकाल रहे थे। भारत इस बात से चिंतित नहीं है कि ट्रंप क्या टेरिफ लगा रहे हैं बल्कि उसके साथ–साथ भारत अपने दूसरे रास्ते भी तलाश रहा है और यही कारण रहा कि भारत ने इयू के साथ जो डील की है और उसके बाद अमेरिका की जो प्रतिक्रिया आई थी डील के बाद जो अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया आई थी उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि अमेरिका को ये डील देख के जरूर है कि भारत ने इतना बड़ा और अपने हित का इतना बड़ा समझौता कैसे कर लिया। वो भी ऐसे वक्त में जब कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका नाटो को आंख दिखा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद और अन्य सामान खरीदेगा।

हकीकत यह है कि भारत अभी अमेरिका से सालाना 50 अरब डॉलर से भी कम का आयात करता है। इस स्तर तक पहुंचने में 20 साल से अधिक का समय लग सकता है। इसलिए यह आंकड़ा किसी पक्के और तुरंत पूरे होने वाले वादे से ज्यादा एक लंबे समय का लक्ष्य लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पोस्ट कई अहम बिंदुओं पर भ्रम पैदा करती है, जिनका स्पष्ट होना जरूरी है। ऐसे में भारत को अभी जश्न नहीं मनाना चाहिए। ट्रम्प का दावा है कि भारत टैरिफ शून्य कर देगा, लेकिन यह साफ नहीं है कि इसमें कौन से उत्पाद हैं? भारत अनाज, जीएम उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी बाजार के लिए खोलने का विरोध करता रहा है।अभी भारत अमेरिका से सालाना 50 अरब डॉलर से कम आयात करता है। ऐसे में 500 अरब डॉलर (45 लाख करोड़ रु.) के लक्ष्य तक पहुंचने में 20 साल लग सकते हैं, जो बताता है कि आंकड़ा केवल लंबी अवधि की इच्छा है, तात्कालिक वादा नहीं। व्यापारिक समझौते बहुत गंभीर विषय होते हैं। जब तक दोनों देशों का संयुक्त बयान और समझौते का मसौदा सामने न आ जाए, तब तक इसे केवल एक राजनीतिक संकेत माना जाना चाहिए, न कि अंतिम समझौता।

दो व्यापार समझौते और तीन चुनौतियां

दीपक

करोड़ों गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी और काम के तय घंटे जैसी बुनियादी चीजें देना भी उसका काम है। और रोजगार भी तभी बढ़ेंगे जब निवेश का तंत्र सुधरेगा। असल में यह खाए, पिए अघाए लोगों का बजट है, अच्छी हालत में भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश करने की जगह चीजों को वैसे ही चलाने देने की सोच का अभाव है, कुछ न करके भी संतुष्ट रहने का बजट है। आखिर अमेरिका से भी व्यापार संधि हो गई और सारी बारीकी सामने नहीं आई हो तब भी यह नतीजा निकालने में हर्ज नहीं है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाले प्रावधान इसमें हैं और 18 फीसदी सीमा शुल्क पर भारतीय माल के अमेरिका प्रवेश का मतलब हमारा व्यापार बढ़ना ही होगा। एक नई बात यह हो सकती है की कुछ अमेरिकीध विदेशी उत्पादक अमेरिका में ही अपना ज्यादा माल बेच सकने की सहूलियत के लिए भारत में अपना प्रोडक्शन बेस बनाएं। अमेरिकी संधि तो बजट के अगले दिन हुई पर यूरोपीय संघ से खुले व्यापार की संधि भी तीन–चार दिन पहले हुई थी। उसके प्रावधान भी यही स्थिति बनाते हैं और यही चीजें इन संधियों का सबसे धनात्मक पक्ष है। अब अमेरिका से समझौते की घोषणा भले दो तारीख को हुई हो लेकिन अधिकांश शर्तों पर सहमति बनाने की चर्चा बिहार चुनाव के पहले से हो रही थी। और तो और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तीन दिन पहले यह कह दिया था कि यह समझौता अब हो जाने को ही है। इस प्रसंग को लंबा खींचने के पीछे यह बात दिखाने की मंशा है कि बजट की तैयारियों के क्रम में इन दो बड़ी संधियों का आधार तैयार था और कम से कम इस बातचीत में शामिल लोगों को तो प्रावधानों की भी लगभग पूरी स्थिति का पता होगा। लेकिन निर्मला सीतारमन के नौवें बजट में इस संधियों के फलितार्थ से संबंधित कोई तैयारी नहीं दिखती। यूरोपीय संघ और अमेरिका हमारे पशुपालन और खेती को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के लिए दबाव बना रहे थे और इनमें से काफी बातें मान ली गई हैं। कार, शराब से लेकर अनेक औद्योगिक उत्पाद का आयात सस्ता होकर हमारे अपने उत्पादन और खपत के परिदृश्य को बदलेगा। बजट में कृषि और पशुपालन या मत्स्य और कुक्कुटपालन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो आगे आने वाले प्रभाव में हमारे किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा कर सके। हम जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में खेती और डेयरी का कारोबार भारी सब्सिडी पर चलता है। ऐसे में गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, जेनेटिक फसलों और खली के धंधे पर ही नहीं दूध, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों पर असर होगा लेकिन वित्त मंत्री ने उसकी चिंता अगले बजट के लिए छोड़ दी है। वे इस बजट को जाने किस आधार पर युवाओं का और नये भारत के निर्माण का बजट बता रही हैं।इससे भी ज्यादा जिस चीज की चिंता करनी चाहिए थी वह है भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ठिकाना बनाने की तैयारी। ये दोनों व्यापार सन्धियां हमारे यहां से तैयार माल को यूरोप और अमेरिका में भेजने का रास्ता सुगम करेंगी। फिर सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर के लिए ही नहीं, सारे औद्योगिक उत्पादों और उपभोक्ता मशीनरी के निर्माण और एसेम्बलिङ्ग कारोबार की राह इससे खुलने वाली है। इस बीच यह भी हुआ है कि ट्रम्प की नीतियों और वैश्विक वित्त बाजार में अनिश्चितता के चलते दुनिया भर की पूंजी विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की तरफ मुड़ गई है। और तो और वहां भी सोना–चांदी में निवेश को सुरक्षित और बढ़ने वाला मानने का चलन बढ़ा है। उनके यहां के निवेश में पांच से बारह फीसदी तक की वृद्धि हुई है जबकि हमारे यहां से बड़ी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में कमी आई है। विदेशी पूंजी की जगह देसी पूंजी ने कुछ समय तक मोर्चा संभाला लेकिन अब उसकी क्षमता की सीमा आ गई है, यह हर आदमी महसूस कर रहा है। बाजार से पूंजी का पलायन रोकने और नई पूंजी को आकर्षित करने वाले कदम उठाने की दरकार है लेकिन निर्मला जी का बजट इस बारे में मौन हो गया है। संरचना क्षेत्र में निवेश अच्छा होता है लेकिन हर जानकार बताता है कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश इस क्षेत्र में कर चुके हैं।पूंजी का पलायन रोकने और नए निवेश को आकर्षित करने जैसा ही इमरजेंसी वाला काम डालर और प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए का धराशायी होना रोकने का है। ऐसी ही आपात जरूरत सर्राफा बाजार के भूचाल को संभालने की है। चांदी भारी सट्टेबाजी की चीज बन गई है और शादियों के मौसम में आम आदमी सोना तो दूर चांदी तक खरीदने की स्थिति में नहीं है और उधर सट्टेबाज माल बनाकर लाल होते गए हैं। एक किलो चांदी की कीमत में एक दिन में अस्सी हजार तक की गिरावट और चढ़ान तो बिना सट्टेबाजी संभव ही नहीं है। और अगर चीन या कोई भी और देश सोना चांदी खरीद कर जमाखोरी कर रहा है तो उसका भी उपाय ढूंढा जाना चाहिए। शेयर बाजार का यही हाल है और बजट के दिन की उसकी दो हजार अंकों की गिरावट को बजट से निराशा मान सकते हैं लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा एक कंपनी को नोटिस देने भर से बाजार लाखों करोड़ के मूल्य गंवा दे यह तो सट्टेबाजों का नहीं उनकी गिरोहबाजी से ही संभव है। रुपया रोज गोते खा रहा है और साल भर में छह फीसदी तक नीचे आ गया है। बजट में इन क्षेत्रों का जिक्र ही नहीं है और प्रतिभूति कारोबार टैक्स बढ़ाकर ऐसा हंगामा मचा दिया गया कि हर आदमी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह क्या बला है। और जो स्थिति समझते हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि इस उपाय से बाजार को क्या फायदा होगा?शायद सरकार महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ने न देने की मंशा को ऊपर रख रही है। उसे जीडीपी की दर और महंगाई दर की चिंता सबसे ज्यादा है। वह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर पर इठला रही है। उसने पिछले बजट में आयकर नियमों में जो बदलाव किए हैं और जो इस बार अप्रैल से लागू होंगे, उनको फाइनल मान लिया है। उसने जीएसटी दरों में जो बदलाव किये उनके बाद कर के ढांचे में मामूली करेक्शनों को छोड़कर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं लगती। वह भूल गई है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना उसी का काम है और दस साल से ज्यादा समय से टल रहा है। अभी के बढ़े टैक्स अपने लोगों से हर साल तीन लाख करोड़ ज्यादा वसूल कर उसके बटुए में पहुंचा देते हैं।

'दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय परम्पराओं में नैतिकता और मूल्य विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन'

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा श्प्राचीन भारतीय परम्पराओं में नैतिकता और मूल्यश विषय पर दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला (कैपिसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप) का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष प्रो. निरंजन कुमार ने प्रश्न उठाया कि आज रोबोटिक्स और ।प् के युग में हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति पर बात करने की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने कहा जो समाज अपनी संस्कृति से कट जाता है, वह उस वृक्ष के समान है जिसकी कोई जड़ ही नहीं होती है। हमारे देश में साजिशन हमारी संस्कृति को भुलाने का कार्य किया गया है। संस्कृति के खिलाफ कई प्रकार के नैरेटिव इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से गढ़े गए। आज इतिहास की पुस्तकों को पुनः लिखे जाने की आवश्यकता है। हमें अपने वेद–उपनिषदों को आज और भी अधिक जानने की आवश्यकता है क्योंकि समाज में यह भ्रम है कि विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य तत्व यूरोप से आए हैं। कहा जाता है कि समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व या लोकतंत्र इत्यादि मूल्य पश्चिम से हमारे यहाँ आए। जबकि सत्य तो यह है कि वेद पुराण, उपनिषद्, बौद्ध और जैन मत आदि में इनका सार स्पष्ट रूप से मौजूद है। आगे प्रो. कुमार ने देश के लिए भारत नाम पर जोर देते हुए कहा कि देर से ही सही लेकिन आज पुनः भारत अपनी अस्मिता को प्राप्त कर रहा है। नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार के समय पहली बार हमने देखा है कि श्प्रेसिडेंट ऑफ भारतश या फिर श्प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारतश का प्रयोग हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक श्री विष्णु त्रिपाठी ने कहा कि नैतिकता और मूल्य भारतीय समाज के डीएनए में रहे हैं। हालाँकि प्रत्येक पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से अधिक तार्किक होती है, लेकिन यदि उसे सही दृष्टि प्रदान की जाए तो निश्चित रूप से वह उन नैतिक मूल्यों को और आगे लेकर जाएगी। नई पीढ़ी को यह दृष्टि प्रदान करने का कार्य हमारे शिक्षकों का है। उन्हों ने कहा कि बहु–अनुशासनिकता हमारी ज्ञान परम्परा में मौजूद रही है. हमारे विद्वान एक साथ संस्कृत, खगोलशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा में महारत रखते थे. यूरोप के पद्धति से अलग हमारे यहाँ ज्ञान खांचो में नहीं बंटा था। हमें अपनी प्राचीन परम्पराओं को अगली पीढ़ी तक लाना चाहिए। आजादी के बाद वाममार्ग या पश्चिमी प्रभाववश सत्ताधारी वर्ग ने कौटिल्य और पतंजलि जैसे दार्शिनिकों को पाठ्यक्रम में न पढ़ाकर अरस्तू और मार्क्स आदि लगाये गए। कार्यक्रम के समापन सत्र के मुख्य अतिथि जम्मू–कश्मीर अध्ययन केंद्र के महासचिव रंजन चौहान जी ने कश्मीर के शारदा पीठ का उदाहरण देते हुए कहा भारतीय संस्कृति में संवाद की प्राचीन परंपरा रही है। आदि शङ्कराचार्य जी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे शारदा पीठ में पाँच आचार्यों से उनका प्रश्नोत्तर और शास्त्रार्थ हुआ था। पाँचों आचार्यों ने उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की। इस परंपरा की आज बहुत जरूरत है। प्रो हीरामन तिवारी, डॉ. बीरेन्द्र प्रसाद डॉ शोभना सिन्हा आदि ने तकनीकी सत्रों में अपना व्याख्यान दिया। प्रो. प्रभात मित्तल और प्रो. रजनी साहनी, डॉ अनन्या बरुआ आदि की आयोजन में प्रमुख भूमिका रही। यहाँ बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्क्रम समिति शिक्षकों के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन लगातार करती रहती है।

संक्षिप्त खबरें

विकसित भारत अभियान के तहत कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु जनपद ने लिया संकल्प

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र के नेतृत्व में जनपद में विकसित भारत अभियान के अंतर्गत कुष्ठ रोग उन्मूलन को लेकर व्यापक जागरूकता एवं संकल्प कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं , जिसके क्रम में उन्होंने जनपद वासियों को संकल्प दिलाते हुए कहा है कि जनपद के लोग और जिला प्रशासन "विकसित भारत अभियान" के अवसर पर यह घोषणा करते हैं कि हम अपने जनपद को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोडेगें। कुष्ठ रोग को पहचानना बहुत आसान है और यह साध्य है। हम सभी कुष्ठ रोगियों को जितनी जल्दी हो सके खोजने के लिए हर संम्भव प्रयास करेगें। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेगें। इसके साथ हम कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेगें और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने देगें। हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से जुडे कलंक और भेदभाव को समाप्त करने और उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देगें। इसके साथ ही प्रतिज्ञा दिलायी कि हम सभी कलंक एवं भेदभाव के प्रति शून्य सहिष्णुता के लिये "भेदभाव समाप्त कर गरिमा सुनिश्चित करेंगे।

जल जीवन मिशन की खुली पोल,लाखों खर्च के बाद भी प्यासा हैं बकचुना गांववासी।

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जिले में हर घर जल का सपना टूट चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्जल जीवन मिशनश जमीनी स्तर पर किस तरह दम तोड़ रही है, इसकी बानगी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालय अमानीगंज के बकचुना गांव में देखने को मिल रही है। यहाँ श्हर घर जलश पहुंचाने के दावे कागजी साबित हो रहे हैं। गांव में बिछाई गई पाइप लाइनें जगह–जगह से टूटी पड़ी हैं, और ग्रामीण बूंद–बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एडवोकेट पवन शुक्ला ने शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने शिकायत में दर्शाया है कि मोहली चौराहा से बकचुना गांव की तरफ आते समय पुलिया पर पाइप टूट गई है जिसके चलते गांव में पानी नहीं आ रहा है। गांव का हालात यह हैं कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद टोंटियों से पानी नहीं टपक रहा है। जल जीवन मिशन का पानी सिर्फ सपना बनकर रह गया है।इस बात को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। समाधान दिवस में मौजूद अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि टूटी पाइप लाइनों की मरम्मत जल्द कराई जाएगी। अब देखना यह है कि समाधान दिवस में मिली शिकायत के बाद प्रशासन कितनी जल्दी इस गांव की प्यास बुझा पाता है।

केंद्रीय बजट 2026 नेशन फर्स्ट की भावना को सशक्त करेगा - प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा जौनपुर के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को निरीक्षण भवन में केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर पत्रकारों से

बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला है और नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के समग्र कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करता है। उन्होंने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताया। ए.के. शर्मा ने बताया कि बजट में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को विशेष प्राथमिकता दी गई है। दिल्लीदृवाराणसी और वाराणसीदृसिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और सेवाओं के विस्तार से बड़ा बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने से आमजन को त्वरित और बेहतर इलाज मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि बजट में नारी सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया गया है। लखपति दीदी योजना के विस्तार और स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कृषि पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक और एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह समावेशी है और देश के संतुलित विकास को नई गति देगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

अन्नपूर्णा भवनों को "सहज जन सुविधा केंद्र" के रूप में विकसित किया जा रहा है

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सरकारी सस्ती राशन की दुकानों को अब नए स्वरूप में विकसित कर "अन्नपूर्णा भवन" बनाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत इन भवनों के संचालन की जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सौंपी गई है। जल्द ही पंचायत विभाग द्वारा इन भवनों को औपचारिक रूप से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2025–26 तक कुल 151 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिले के 87 गांवों में भूमि की पहचान कर ली गई है। इनमें से 64 भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा, जबकि 23 भवन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा निर्मित कराए जाएंगे। प्रत्येक भवन पर करीब 8.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। पंचायत भवनों को जन सुविधा केंद्रों में बदलने की तर्ज पर, इन अन्नपूर्णा भवनों को भी "सहज जन सुविधा केंद्र" के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां से जरूरतमंदों को भू–अभिलेख सहित अन्य आवश्यक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रथम चरण में मॉडल के तौर पर 75 राशन की दुकानों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 65 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिले में कुल 1734 ग्राम पंचायतें हैं और सरकार इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक गांव तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। जिले में कुल 2010 सस्ती राशन की दुकानें हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नया प्रावधान भी किया गया है। अब सांसद या विधायक भी अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव दे सकेंगे, जिस पर शासन स्तर पर विचार कर निर्माण कराया जाएगा। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। वर्ष 2023–24 में 75 भवनों का लक्ष्य रखा गया था और इसी तरह 2025–26 के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। योजना को प्रभावी बनाने और निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को अलग से बजट भी आवंटित किया गया है।

संक्षिप्त खबरें

फॉर्म–7 के दुरुपयोग पर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो होगा बड़ा आंदोलन : राकेश मौर्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,07 फरवरी। यूपी के जौनपुर स्थित समाजवादी पार्टी की जिला इकाई की मासिक बैठक शनिवार को सदर चुंगी अलफस्टीनगंज स्थित जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (ैप्) प्रक्रिया के अंतर्गत भाजपा नेताओं द्वारा फॉर्म–7 के कथित दुरुपयोग को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत करते हुए जिला महासचिव आरिफ हबीब ने सदन को एजेंडे से अवगत कराया। उन्होंने ैप् के तहत फॉर्म 6, 7 और 8 की समीक्षा, बढ़ी हुई तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों, नोटिस व आपत्तियों के निस्तारण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कराई। अध्यक्षीय संबोधन में जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ैप् कार्य को शत–प्रतिशत सफल बनाने के उद्देश्य से दूसरे चरण में एक माह का समय दिया गया है, ताकि शेष पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा नेताओं द्वारा फॉर्म–7 का बल्क में दुरुपयोग किया जा रहा है और विशेष रूप से अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए ठस्र पर दबाव बनाया जा रहा है। राकेश मौर्य ने कहा कि इस संबंध में लिखित शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक और रोल प्रेक्षक (कमिश्नर) को दी जा चुकी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने फॉर्म–7 के दुरुपयोग पर तत्काल रोक नहीं लगाई तो समाजवादी पार्टी को बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। बैठक में ैप् कार्य में सक्रिय रूप से योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। वहीं विधानसभा क्षेत्र सदर के चौकियां निवासी विनय एडवोकेट को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बैठक को पूर्व विधायक राजनरायन बिंद, श्रद्धा यादव सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

कलेक्ट्रेट में तैनात राज कपूर बने प्रशासनिक अधिकारी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ अयोध्या)

अयोध्या।कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात राज कपूर श्रीवास्तव की

पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हुई।राज कपूर श्रीवास्तव की पदोन्नति प्रशासनिक पद पर होने की खबर मिलने पर कलेक्ट्रेट परिसर में हर्ष की माहौल दिखाई दिया।उनके पदोन्नति पर कलेक्ट्रेट के कर्मियों ने उन्हें शुभकामना दिया।उनके पदोन्नति होने पर चित्रांश सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष कैलाश लाल श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव,अजीत श्रीवास्तव सहित कई लोगों ने शुभकामना दिया।

तहसील टॉस्क फोर्स की बैठक एसडीएम की अध्यक्षता मे संम्पन

अयोध्या।एसडीएम सोहावल सविता देवी की अध्यक्षता में तहसील टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई।बैठक का संचालन अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौधा डॉ प्रदीप कुमार और ब्लॉक मोबिलाइजर कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ ब्लॉक मसौधा धीरेंद्र नाथ पाण्डेय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मसौधा राजीव प्रकाश चतुर्वेदी द्वारा बताया गया फरवरी माह में तीन प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तावित है. पहला एम डी. ए. प्रोग्राम जो 10 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य संचालित होंगे मसौदा ब्लॉक के अंतर्गत 8 ग्राम सभा में इसमें आशा और आंगनबाड़ी और एनम द्वारा घर–घर फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस जो की 10 फरवरी को प्रत्येक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल मद्रास में 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाएगी छूट गए बच्चों को 13 फरवरी को खिलाई जाएगी।तीसरा कार्यक्रम मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान यहां प्रोग्राम 16 फरवरी 20 26 से 27 फरवरी 2026 तक तक चलेगा इस अभियान में कक्षा 1 से लेकर 5 तक में पढ़ने वाले बच्चों को उक्त टीका लगाया जाएगा इसमें सरकारी गैर सरकारी और मदरसा को कवर किया जाएगा।बैठक के दौरान ब्लॉक मोबिलाइजर यूनिसेफ धीरेंद्र नाथ पाण्डेय ब्लॉक मसौधा द्वारा बताया गया नगर पंचायत एरिया भरत कुंड भदरसा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार द्वारा बताया गया उक्त से संबंधित अभिमुखीकरण समस्त आंगनबाड़ी वर्कों का अभिमुखीकरण 7 फरवरी 2026 को आंगनवाड़ी विभाग में कराया गया है।सरकारी गैस सरकारी विद्यालयों के नोडल अध्यापकों का अभिमुखीकरण आगामी 9 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो बैच में किया जाएगा. आज की बैठक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिशा संस्था ब्लॉक मसौधा राजाराम द्वारा अपने संस्थान के द्वारा सहयोग करने का वायदा किया और संस्था द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं के बारे में समस्त को अवगत कराया सलोनी संगम किशोरी लड़कियों की देखरेख. बाल क्लब बच्चों का समूह. विशेष बच्चों की देखभाल. किसानों की देखरेख राजाराम द्वारा यूपी जिला अधिकारी को नया साल 2026 का कैलेंडर डायरी भेद किया गया।बैठक में ब्लॉक सोहावल और मसौधा अधीक्षक. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सहायक शोध अधिकारी.अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत,खंड विकास अधिकारी,सहायक विकास अधिकारी पंचायत खंड शिक्षा अधिकारी,सप्लाई इंस्पेक्टर,बाल विकास परियोजना अधिकारी. विश्व स्वास्थ्य संगठन के ब्लॉक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बकाया गृहकर जमा न करने पर मंडी परिषद का खाता सीज

लखनऊ, (संवाददाता)। करीब 65 लाख रुपये का बकाया गृहकर न जमा करने पर नगर निगम ने बृहस्पतिवार को मंडी परिषद का बैंक खाता सीज कर दिया। एक सप्ताह में कर जमा नहीं किया तो खाते से कटौती कर ली जाएगी। जोन छह के जोनल अधिकारी अमरजीत यादव ने बताया कि दुबग्गा सब्जी मंडी और मछली मंडी पर कई वर्षों का गृहकर बकाया है। यह टैक्स पुनरीक्षित करने के बाद का है। परिषद को कई बार बिल और नोटिस जारी करने के साथ टीम ने कार्यालय जाकर भी संपर्क किया, लेकिन गृहकर नहीं जमा किया गया। इस कारण बृहस्पतिवार को सीतापुर रोड स्थित नवीन मंडी समिति की एसबीआई शाखा में मंडी परिषद के खाते को सीज कर दिया गया। मंडी परिषद अब इससे लेन–देन नहीं कर पाएगी। जोनल अधिकारी ने बताया कि 19 जनवरी को मंडी परिषद की ओर से 22 लाख रुपये का चेक व्हाट्सएप से बिना साइन का भेजा गया, पर मूल चेक नहीं जमा कराया गया। इसे लेकर भी आपत्ति की गई थी।

एयरफोर्स स्टेशन की बत्ती गुल होने पर मेरठ के तीन एसडीओ निलंबित

लखनऊ, (संवाददाता)। मेमौरा एयरफोर्स स्टेशन की बिजली गुल होने और 11 करोड़ की लाइन के निर्माण में गड़बड़ी बरतने के आरोप में मेरठ विद्युत वितरण निगम के तीन एसडीओ (उपखंड अधिकारी) निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें से दो बतौर जूनियर इंजीनियर और एक एसडीओ के रूप में लखनऊ में तैनात रह चुके हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ की एमडी रिया केजरीवाल की ओर से 24 जनवरी को लिखे पत्र पर मेरठ विद्युत वितरण निगम के एमडी रवीश गुप्ता ने कार्रवाई की। निलंबित होने वालों में गाजियाबाद के उपखंड लालबाग लोनी के आनंद कुमार, उपखंड गुन्नौर संभल के ऋषि शुक्ला और अमरोहा उपखंड के सतविंदर कुमार यादव हैं। इनमें से आनंद व ऋषि लेसा निर्माण सर्किल में जूनियर इंजीनियर थे। सतविंदर मोहनलालगंज उपखंड में एसडीओ रह चुके हैं। तीनों को सहारनपुर मुख्य अभियंता जोन कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

इंदिरानगर में बदली जाएगी टूटी सीवर लाइन

लखनऊ, (संवाददाता)। इंदिरानगर में टूटी गहरी सीवर लाइन की मरम्मत का काम ट्रेंच लेस तकनीक से होगा। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे तकनीकी मंजूरी के लिए जलकल विभाग ने जल निगम को भेजा है। सीवर लाइन पड़ने से गोमतीनगर वार्ड की लक्ष्मणपुरी कॉलोनी और आसपास के इलाके में सीवर की समस्या दूर होगी। पार्षद कौशल शंकर पांडेय ने बताया कि मेट्रो के काम के वक्त अयोध्या रोड पर पिलर बनाने के दौरान सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। तबसे लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में सीवर चोक की समस्या है। पाइप लाइन टूटी होने से सीवर लाइन में ही भरा रहता है। शिकायत पर सुएज की गाड़ी मैनहोल से गंदगी खींचकर ले जाती है। दो दिन में फिर वही हाल हो जाता है। मेन लाइन की मरम्मत न होने से कॉलोनी के 250 घरों में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लोगों को टैंक से काम चलाना पड़ रहा है। पार्षद ने बताया कि 27 जनवरी को नगर निगम सदन में मामला उठाया गया था। जलकल के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि इंदिरानगर ए ब्लॉक में क्रोमा शोरूम से नीलगिरि चौराहे तक सात मीटर गहराई में 140 मीटर लाइन डालने के प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है। 800 एमएम डाया की 70 मीटर लंबी सीवर लाइन को और डाला जाना है। मेन रोड पर आवागमन रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण ट्रेंच लेस तकनीक से काम होगा। इसकी मंजूरी मिलने के तीन महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा।

'सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करायें–अनुनय झा'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' शनिवार को तहसील शाहाबाद सभागार में आहूत सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने उपस्थित जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करायें और प्रत्येक दिन कार्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे के बीच रहकर विभागीय शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय में निष्पक्ष तथा गुणवत्ता पूर्ण करायें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी कानूनगों एवं लेखपालों को निर्देश दिये कि सभी तरह की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को चिन्हित करें और अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस के सहयोग से गरीबों एवं सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करायें और कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। विद्युत विभाग की शिकायतों के संबंध में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खराब ट्रांसफार्मर एवं जर्जर विद्युत लाइनें तत्काल ठीक करायें और नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति करायें तथा विद्युत उपभोक्ताओं के बिल आदि की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करायें। पेंशन की शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन निराश्रित, वृद्ध एवं दिव्यांगजन की पेंशन किसी कारण बंद हो गयी उसकी जांच करायें और पात्र लोगों की पेंशन बहाल कराने के साथ नये पेंशन आवेदन पत्रों के संबंध में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें। राशन वितरण में अनियमिताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों से संबंधित राशन दुकानों की जांच करायें और शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित कोटेदार के विरूद्ध कार्यवाही करें। अन्य विभागों की प्राप्त शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कहा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण ससमय हो और निस्तारण की जानकारी शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करायें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने उपस्थित थानाध्यक्षों को निर्देश दिये ।

यदि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो ऐसे मंत्रियों विधायकों सांसदों को पहले पद से इस्तीफा दे देना चाहिए : ओम प्रकाश राजभर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर शुक्रवार को एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पीडीए के वोट काटे जाने का आरोप पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल ओमप्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, संजय चौहान और अनुप्रिया पटेल भी पीडीए वर्ग से आते हैं, फिर उनके वोट क्यों नहीं कट रहे? राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सड़कों पर बयानबाजी कर समाज को गुमराह

कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बूथ स्तर पर सपा के कार्यकर्ता वोट बढ़ाने, कटवाने और नाम संशोधन का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर सरकार का नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का कार्य है और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता से प्रक्रिया संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने समयसीमा भी बढ़ाई है और यह भरोसा दिया है कि बिना सूचना के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को गलत बताते हुए राजभर ने कहा कि जो नेता इसी आयोग के जरिए सांसद–विधायक बने हैं, उन्हें पहले नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि आयोग पर भरोसा नहीं है तो ऐसे नेताओं को पहले इस्तीफा देना चाहिए। राजभर ने आगामी चुनावों को लेकर कहा कि 22 फरवरी को आजमगढ़ के अहिरौला गांव में बड़ी जनसभा कर 2027 के चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और समय पर चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है और 28 फरवरी को अंतिम प्रकाशन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 62 सीटों पर तैयारी कर रही है और बूथ, सेक्टर व विधानसभा स्तर तक संगठन मजबूत किया गया है। भाजपा को बड़ी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि सीटों का फैसला आपसी सहमति से होगा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि 2027 में सपा की स्थिति 2017 से भी कमजोर होगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विकास के मुद्दों पर बात करने के बजाय केवल आरोप–प्रत्यारोप किया जा रहा है,

अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अंबेडकरनगर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया

अयोध्या (ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार अयोध्या प्रदर्शन का नेतृत्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. जन्मेजय तिवारी ने किया। मामला बीएनकेबी परीक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ बताया गया। दो दिन पूर्व अंबेडकरनगर की एसडीएम प्रतीक्षा सिंह ने परीक्षा केंद्र पर छापा मारा। शिक्षक संघ का आरोप है कि छापे के दौरान केंद्र अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। छापेमारी में परीक्षा केंद्र से कोई भी नकल सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बावजूद केंद्र अध्यक्ष के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। शिक्षक संघ का कहना है कि जिला प्रशासन को विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों पर छापा मारने का अधिकार नहीं है। परीक्षाओं की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति और उड़ाका दल नियुक्त किए जाते हैं। मुकदमा वापस नहीं लेने पर शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

अयोध्या में भारतीय सेना की मॉक ड्रिल:आपदा में त्वरित चिकित्सा व्यवस्था का अभ्यास

अयोध्या(ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या आपदा की घड़ी में एक–एक सेकेंड कितना कीमती होता है।इसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में भारतीय सेवा के जवानों द्वारा एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य थाकृ किसी भी आपात स्थिति में त्वरित, संगठित और प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए, इसका वास्तविक अभ्यास। ड्रिल के दौरान इंडियन आर्मी के जवानों ने पहले जिला चिकित्सालय में एक स्मार्ट ड्रिल का पूरा दृश्य प्रस्तुत किया। यह दिखाया गया कि आपदा या बड़े हादसे की स्थिति में घायल व्यक्ति को कैसे सुरक्षित तरीके से अस्पताल लाया जाएगा, कैसे रैपिड ट्रायेज किया जाएगा, और किस तरह कुछ ही मिनटों में जीवन रक्षक उपचार शुरू किया जाएगा।

मॉक ड्रिल में यह भी प्रदर्शित किया गया कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बीच समन्वय ,एंबुलेंस और मेडिकल टीम की तैनाती प्राथमिक उपचार से लेकरइमरजेंसी सर्जरी तक की तैयारीकितनी अहम होती है।भारतीय सेना के जवानों नेडमी मरीजों के माध्यम सेघायलों को उठाने,स्ट्रेचर से ले जाने,और इमरजेंसी वार्ड तक पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया। इस अभ्यास का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि यदि कभी वास्तविक आपदा आती है, तो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हों। इस मॉक ड्रिल ने न सिर्फ अस्पताल की तैयारियों को परखा, बल्कि यह संदेश भी दिया किसमय पर सही इलाज कई जिंदगियाँ बचा सकता है। अयोध्या में आयोजित यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की दिशा में एक अहम और सराहनीय कदम माना जा रहा है।

राजस्व वसूली में फिसड्डी निरीक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण

अयोध्या(क्राइम रिपोर्टर) संतोष कुमार। राजस्व वसूली के मामले में लापरवाही बरतने वाले दो निरीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही नगर निगम ने बड़े बकाएदार होटल संचालकों से सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम कार्यालय में महापौर गिरीश पति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार ने कर–करेत्तर संबंधी समीक्षा बैठक क, जिसमें नगर आयुक्त ने बकाया राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग समेत सभी सरकारी विभागों को बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजा गया है। इस दौरान नगर आयुक्त ने 14 कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों से टैक्स वसूली करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली विभाग के डिविजनल मैनेजर से वार्ता के क्रम में निर्देशित किया कि शहर में लगे ट्रांसफार्मर के कवर एरिया या प्लाट पर टैक्स निर्धारण कर उन्हें अवगत कराएं, ताकि बिजली विभाग से ससमय कर जमा कराया जा सके। नगर आयुक्त ने कर अधीक्षकों एवं राजस्व निरीक्षकों को हिदायत दी कि नागरिकों की ओर से शिकायत आ रही है कि पहले ज्यादा टैक्स लगाकर फिर कम करने के नाम पर अनुचित मांग की जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कम राजस्व वसूली के कारण अयोध्याधाम के राजस्व निरीक्षक गोविंद प्रकाश पांडे एवं शमशेर सिंह को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश जोनल अधिकारी को दिया। नगर आयुक्त ने अवधपुरी जोन की राजस्व निरीक्षक श्रीमती स्वप्निल सिंह से शाश्वत एवं पुष्पक जैसे होटल के टैक्स को लेकर चर्चा की। उनके द्वारा स्पष्ट जवाब न दिए जाने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। राजस्व निरीक्षक प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रमुख होटलों को नोटिस डिमांड तैयार कर भेजा जा रहा है। महापौर एवं नगर आयुक्त ने अयोध्या धाम में कार्यरत कर्मचारी भोला गुप्ता एवं ओमप्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध मिल रही शिकायतों के मद्देनजर हटाने का निर्देश जोनल अधिकारी को दिया। इस दौरान नरेंद्रालय में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था किए जाने एवं वहां से निष्प्रयोग वाहनों को हटाने के लिए भी महापौर ने अपर आयुक्त को निर्देशित किया। इसके साथ ही कर अधीक्षक जय प्रकाश को करेक्टर मद में वाहन पार्किंग तथा विज्ञापन की वसूली बढ़ाने एवं बकाया धनराशि को शीघ्र जमा करने के लिए निर्देशित किया। यह भी कहा गया कि सभी जोनल अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में नए भवनों को शत–प्रतिशत कर के दायरे में लाएं। बैठक में अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार, जोनल अधिकारी अशोक कुमार गुप्त, सौरभ नाथ, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार, कर निर्धारण अधिकारी विनय प्रताप सिंह, कर अधीक्षक जयप्रकाश, विनय कुमार गौड़, राजस्व निरीक्षक अनिल यादव, देवीप्रसाद, वीरेंद्र पटेल, गोविंद प्रकाश पांडे, शमशेर सिंह, स्वप्निल सिंह, प्रतिमा श्रीवास्तव, वंदना आदि की मौजूदगी रही।

संक्षिप्त खबरें

अयोध्या मेडिकल कॉलेज से हटाए गए प्राचार्य डॉ सत्यजीत वर्मा के विरुद्ध शिकायत

अयोध्या (ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार मेडिकल कॉलेज से हटाए गए प्राचार्य डॉ सत्यजीत वर्मा के विरुद्ध शिकायत व साक्ष्य संदेह के घेरे में, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जांच के आदेश दिए हैं, प्रभारी प्राचार्य डॉ दिनेश सिंह मर्तोलिया ने छह सदस्यीय जांच गठित कमेटी बनाई है, कॉलेज के ही छह प्रोफेसर डॉ पारस खरबंदा, डॉ डीके सिंह, डॉ अरविंद कुमार, डॉ प्रतिभा गुप्ता, डॉ स्नेहांशु, डॉ अंजू सिंह ने भेजी थी शिकायत, शिकायत भेजने वालों में डॉ ज्ञानेंद्र कुमार, प्रीती खरबंदा के साथ दो लैब टेक्नीशियन उमाशंकर, संतोष और समर बहादुर पटेल का भी नाम सामने आया, संदेह जताते हुए तथ्यों के साथ अधिवक्ता चंद्र शर्मा ने भेजी थी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव समेत अन्य को शिकायत, मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ लोकायुक्त जांच कराने की भी मांग की है प्राचार्य के जांच कमेटी गठित करते ही हड़कंप मचा गया, प्रोफेसर्स के शिकायत के बाद ही तत्कालीन प्राचार्य डॉ सत्यजीत वर्मा हटाए गए।

फिल्म घूसखोर पंडत पर बढ़ा आक्रोश : बीकापुर में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, FIR और बैन की मांग

बीकापुर, अयोध्या। (क्राइम रिपोर्टर) संतोष कुमार। फिल्मों और डिजिटल कंटेंट के नाम पर सनातन संस्कृति और विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाने के खिलाफ अब अयोध्या जनपद में भी स्वर मुखर होने लगे हैं। हाल ही में चर्चा में आई फिल्म श्घूसखोर पंडतश के शीर्षक और उसमें दिखाए गए चित्रण को लेकर ब्राह्मण समाज और सनातन धर्मावलंबियों में भारी रोष व्याप्त है। शनिवार को इस फिल्म के विरोध में प्रबुद्ध नागरिकों ने बीकापुर तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी श्रेया को राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। सनातन संस्कृति के अपमान का आरोप अयोध्या जी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान संदीप तिवारी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि फिल्म का शीर्षक न केवल अमर्यादित है, बल्कि यह जानबूझकर ब्राह्मण समाज की छवि को धूमिल करने के लिए गढ़ा गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक विशिष्ट वर्ग को श्भ्रष्टश दिखाकर समाज में जातिगत विद्वेष फैलाने की साजिश रची जा रही है। फिल्म के निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों के विरुद्ध थ्प्त दर्ज कर कठोर विधिक कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए फिल्म के प्रसारण पर तत्काल प्रतिबंध (ठंद) लगाया जाए। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कंटेंट पर भविष्य में रोक हेतु कड़े निर्देश जारी हों। मौके पर उपस्थित रहे वरिष्ठ भाजपा नेता हैदरगंज के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेन्द्र मिश्रा ने कहा कि समाज के शांतिपूर्ण ताने–बाने को छिन्न–भिन्न करने वाले ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से हरिओम दुबे बीकापुर शैलेंद्र पांडे मोनू डा श्याम तिवारी शैलेंद्र शुक्ला, सुरेश मिश्रा दीपू मिश्रा, एडवोकेट श्रीकांत तिवारी अधिवक्ता पुष्पेंद्र मिश्रा अधिवक्ता हरिओम पांडे अविनाश मिश्रा, शिवम पांडेय, अथर्व तिवारी उत्सव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे सभी ने एक स्वर से सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग की।

अयोध्या जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर के साथ तहसील मिल्कीपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

अयोध्या (ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या जिलाधिकारी ने समाधान दिवस के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। तहसील मिल्कीपुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत अगरवा में राशन कार्ड में नाम न जोड़ने की शिकायत की है, जिस पर जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक को जांच कर राशन कार्ड बनाने को कहा। शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत चांदपुर में जमीन की पैमाइस कराने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को टीम बनाकर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी तरह ग्राम पंचायत बरईपारा में भूमि विवाद व ग्राम पंचायत तरौली में रास्ते को बंद करने की शिकायत की जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को न्यायोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने मिल्कीपुर सम्पूर्ण समाधान दिवस में आज कुल 161 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तहसील दिवस में मुख्यतः भूमि विवाद, राजस्व, सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेंशन आदि से संबंधित अधिकतर शिकायतें प्राप्त हुईं, इसके निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए गए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिला पूर्ति अधिकारी, उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर, खण्ड विकास अधिकारी मिल्कीपुर, तहसीलदार मिल्कीपुर व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

पीयू में संबद्धता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च तक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता नवीनीकरण प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न होने पर संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कुलसचिव केशलाल ने शनिवार को बात करते हुए बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विषयों और पाठ्यक्रमों की संबद्धता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च तय की गई है। विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को समय से आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में यह भी बताया गया है कि संबद्धता प्रस्तावों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण मंडल का गठन 25 मार्च तक किया जाएगा। विशेष रूप से वे महाविद्यालय, जिनकी अस्थायी संबद्धता 30 जून को समाप्त हो रही है, उन्हें निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि संबद्धता नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं की जाती है, तो संबंधित विषयों और पाठ्यक्रमों में 1 जुलाई से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इससे महाविद्यालयों और विद्यार्थियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्ष 2023 के बाद पीयू के स्नातक परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं को अब प्लास्टिक कोटेड डिग्री प्रदान की जाएगी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,07 फरवरी। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने उपाधियों को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2023 के बाद स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं को अब प्लास्टिक कोटेड डिग्री प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इससे पहले उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को पूर्व की तरह कागज पर मुद्रित डिग्री ही दी जाएगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य उपाधियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और छेड़छाड़ की संभावनाओं को समाप्त करना है। कागज की डिग्रियों के फटने, खराब होने या नष्ट होने की आशंका बनी रहती है, जबकि प्लास्टिक कोटेड डिग्री अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। नई व्यवस्था से छात्र–छात्राओं को रोजगार, उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन के दौरान सहूलियत मिलेगी।।इस मामले शनिवार को बात करते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्लास्टिक कोटेड उपाधि टूटने या खराब होने की स्थिति में भी सुरक्षित रहती है और इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी संभव नहीं है। डिग्री में एक विशेष गुप्त कोड अंकित रहेगा, जिसे केवल विभागीय स्तर पर ही सत्यापित किया जा सकेगा। छेड़छाड़ की स्थिति में तुरंत उसकी पहचान हो जाएगी।प्लास्टिक कोटेड डिग्री की सत्यता जांचना भी अपेक्षाकृत आसान होगा।

संपूर्ण समाधान दिवस पर 129 शिकायते प्राप्त मौके पर 04 का त्वरित निस्तारण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 07 फरवरी। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में तहसील मछलीशहर के सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के द्वारा शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक सुनते हुए निस्तारित किया गया और अवशेष को सम्बन्धित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए गुणवत्तापूर्ण और ससमय निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। ग्राम घिसुआं की दुलारी देवी के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रार्थी के पति जीवित है और गांव में एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण उन्हे मृतक दिखाकर वरासत दूसरे के नाम कर दी गयी है जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया कि शीघ्र अति शीघ्र जांचकर त्रुटि का निस्तारण करते अवगत कराये। ग्राम गडवादोदक निवासिनी फातमा बेगम ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से नये राशन कार्ड बनाये जाने का अनुरोध किया जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि पात्रता की जांच करते हुए राशन कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें। चकघसीटा के त्रिभुवन के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि बेदखली के आदेश के बावजूद अभी तक तालाब खाते की भूमि से अतिक्रमण नही हटाया गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शिकायत का शीघ्र निस्तारण कर अवगत कराये। घिसुआं निवासी रेखा द्वारा वारासत दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जिसपर जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को शीघ्र वरासत दर्ज करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी के समक्ष कुल 129 शिकायते प्राप्त हुई जिसपर मौके पर 04 का त्वरित निस्तारण कर दिया गया और शेष को सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। इसके उपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा तहसील स्थित विभिन्न कार्यालयों और पटलों का निरीक्षण किया गया। न्यायालय उप जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान लम्बित पुरानी पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये। दाखिल दफ्तर हेतु लंबित पत्रावलियों के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि जो फाइलें अभी भी अवशेष है उनमें ससमय दाखिल दफ्तर की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई। संग्रह कार्यालय और रिकार्ड रुम के निरीक्षण के दौरान लम्बित पत्रावलियों, आनलाइन आरसी, स्टाम्प रजिस्टर, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, खसरा, खतौनी सहित अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया और जानकारी ली गयी और आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। इस दौरान जिलाधिकारी के समक्ष मछलीशहर के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा तहसील परिसर में शौचालय बनवाने हेतु और साफ–सफाई हेतु अनुरोध किया गया जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा ईओ को निर्देशित किया गया कि तहसील परिसर में नियमित रूप से साफ सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही परिसर में बने पिंक शौचालय को क्रियाशील करने और एक नवीन शौचालय बनवाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा वृद्ध फरियादी विद्यावती द्वारा पेंशन हेतु अनुरोध किया गया जिसपर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल पेंशन हेतु पात्रता की जॉचकर अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश देने के साथ ही अन्य वृद्धजन में कम्बल भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी मछलीशहर सौरभ कुमार, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा, उपनिदेशक कृषि, डीडीओ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 ओ0पी0 श्रीवास्तव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक में बड़े बकाएदार होटल संचालकों पर महापौर ने सख्ती करने के दिये निर्देश

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ अयोध्या)

अयोध्या।राजस्व वसूली के मामले में लापरवाही बरतने वाले दो निरीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही नगर निगम ने बड़े बकाएदार होटल संचालकों से सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम कार्यालय में महापौर गिरीश पति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार ने कर–करेत्तर संबंधी समीक्षा बैठक क, जिसमें नगर आयुक्त ने बकाया राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया।समीक्षा के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग समेत सभी सरकारी विभागों को बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजा गया है। इस दौरान नगर आयुक्त ने 14 कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों से टैक्स वसूली करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली विभाग के डिविजनल मैनेजर से वार्ता के क्रम में निर्देशित किया कि शहर में लगे ट्रांसफार्मर के कवर एरिया या प्लाट पर टैक्स निर्धारण कर उन्हें अवगत कराएं, ताकि बिजली विभाग से ससमय कर जमा कराया जा सके। नगर आयुक्त ने कर अधीक्षकों एवं राजस्व निरीक्षकों को हिदायत दी कि नागरिकों की ओर से शिकायत आ रही है कि पहले ज्यादा टैक्स लगाकर फिर कम करने के नाम पर अनुचित मांग की जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कम राजस्व वसूली के कारण अयोध्याधाम के राजस्व निरीक्षक गोविंद प्रकाश पांडे एवं शमशेर सिंह को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश जोनल अधिकारी को दिया।नगर आयुक्त ने अवधपुरी जोन की राजस्व निरीक्षक स्वप्निल सिंह से शाश्वत एवं पुष्पक जैसे होटल के टैक्स को लेकर चर्चा की। उनके द्वारा स्पष्ट जवाब न दिए जाने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। राजस्व निरीक्षक प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रमुख होटलों को नोटिस डिमांड तैयार कर भेजा जा रहा है।महापौर एवं नगर आयुक्त ने अयोध्या धाम में कार्यरत कर्मचारी भोला गुप्ता एवं ओमप्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध मिल रही शिकायतों के मद्देनजर हटाने का निर्देश जोनल अधिकारी को दिया। इस दौरान नरेंद्रालय में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था किए जाने एवं वहां से निष्प्रयोग वाहनों को हटाने के लिए भी महापौर ने अपर आयुक्त को निर्देशित किया।इसके साथ ही कर अधीक्षक जय प्रकाश को करेक्टर मद में वाहन पार्किंग तथा विज्ञापन की वसूली बढ़ाने एवं बकाया धनराशि को शीघ्र जमा करने के लिए निर्देशित किया। यह भी कहा गया कि सभी जोनल अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में नए भवनों को शत–प्रतिशत कर के दायरे में लाएं।बैठक में अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार, जोनल अधिकारी अशोक कुमार गुप्त, सौरभ नाथ, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार, कर निर्धारण अधिकारी विनय प्रताप सिंह, कर अधीक्षक जयप्रकाश, विनय कुमार गौड़, राजस्व निरीक्षक अनिल यादव, देवीप्रसाद, वीरेंद्र पटेल, गोविंद प्रकाश पांडे, शमशेर सिंह, स्वप्निल सिंह, प्रतिमा श्रीवास्तव, वंदना आदि की मौजूदगी रही।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।